B- 3 & 4
L - 16
Social Justice

Mental Health Care Act - 2017

उद्देश्य :

मानसिक तौर पर बीमार लोगों के इलाज और सेवा को सुनिश्चित करना।

- आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।

प्रमुख प्रावधान / लक्षण :-

- सभी सरकारी अस्पतालों में मानसिक तौर से इलाज का अधिकार तथा बेघर एवं गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का प्रावधान (धारा - 18)।
- मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को लिखित रूप से यह निर्धारित करने का अधिकार कि उसका इलाज और देखभाल किस प्रकार से किया जाये (धारा - 18)।
- मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल हेतु 'प्रतिनिधि' की नियुक्ति का प्रावधान (धारा - 14)
- आत्महत्या का प्रयास करने के मामले को एक मानसिक बीमारी मानते हुए, ऐसे मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर

KGS IAS

Scanned by CamScanner

करने और पीड़ित व्यक्ति को सजा न देने का प्रावधान - यदि वह गहरे अवसाद एवं परेशानियों के कारण आत्महत्या कर रहा है तो (धारा-115) (पहले IPC की धारा - 309 के तहत आत्महत्या को अपराध माना जाता था।)

- समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार भेदभाव से निषेध का अधिकार तथा क्रूर, अमानवीय एवं अपमान जनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार।
- मानसिक रोगी को यह तय करने का अधिकार की - इसकी कौन जानकारी मीडिया को नहीं दी जायेगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन तथा राज्यों में भी इसके गठन का प्रावधान। (धारा - 33 एवं 45)
- Mental health Review Board के गठन का प्रावधान, जिससे मानसिक रोगी के अधिकारों की रक्षा की जा सके और समय रहते उचित निर्देश दिये जा सके (धारा - 73)
- कानून के उल्लंघन पर 6: माह जेल या 10 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान और

Scanned by CamScanner

अपराध दोहराने पर 5 लाख तक जुर्माना या 2 वर्ष का जेल या दोनों का प्रावधान (धारा- 107 से 109)।

इन अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए मेंटल हेल्थ केयर चलाने का प्रावधान।

↓

(2023 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अमेंडमेंट अधिनियम /बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें 2017 के कानून में कुछ एक संशोधन किये गए हैं।

समीक्षा / निष्कर्ष

निश्चित रूप से यह अधिनियम मानसिक रूप से बीमार लोगों के प्रति लोक कल्याणकारी राज्य की चिंता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है और इनके कल्याण एवं रक्षोपाय का प्रावधान करता है।

परन्तु इस अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसको दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तथा विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए।

Scanned by CamScanner

क्योंकि अधिकांश राज्यों में अभी तक मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड तथा मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना नहीं की गयी है।

- Feb 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत के कई स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

8 जुलाई 2024 को दिव्यांग के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एवं दिशानिर्देश :-

विजुअल मीडिया से जुड़े क्रिएशन में भेदभाव करने या दिखाने वाले शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए जैसे- लूला, लगड़ा, अंधा आदि।

- ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचे जो दिव्यांगों के द्वारा सामना की गई चुनौतियों की उपेक्षा करती हो और लोगों को उनके बारे में अधूरी जानकारी देती हो।
- विजुअल मीडिया क्रिएटर्स सुनिश्चित करें कि उनके पास उस दिव्यांग से जुड़ी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं।

Scanned by CamScanner

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति : प्रमुख लक्षण

- विकलांगता की रोक थाम पर बल।
- विकलांगों के पुनर्वास पर बल - इस पुनर्वास को तीन श्रेणीयों में बांटा गया है -

(i) शारीरिक पुनर्वास

(ii) सामाजिक पुनर्वास

(iii) आर्थिक पुनर्वास

- विकलांग महिलाओं के शोषण से रक्षा पर बल।
- विकलांग बच्चों की देख-रेख एवं सुरक्षा पर बल।
- विकलांगता का प्रमाणपत्र जारी करना।
- इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन।
- विकलांगता से जुड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना एवं उनका अनुसंधान करना।
- इनके लिए खेल कूद मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन को सुनिश्चित करना
- विकलांगता से संबंधित वर्तमान कानून में संशोधन करना।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

इस नीति के कार्यान्वयन एवं समन्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के DEPOT को उत्तरदायी बनाया गया है।

दिव्यांग जनों के विकास एवं कल्याण हेतु योजनागत प्रयास :-

1. Assistance to Disabled Persons For Purchase/ Fitting of Aids and Appliances (ADIP - 1988/2017 DEPD)

NGO तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दिव्यांग जनों को आधुनिक सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराकर उनका शारीरिक पुनर्वास करना।

2. Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) - 1999, 2018

(दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु दिव्यांग जनों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए काम करने वाले NGO को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।

3. सुगम्य भारत अभियान - 2015

(विकलांग व्यक्तियों को समान अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने एवं

Scanned by CamScanner

आत्मनिर्भरतापूर्वक जीवन जीने और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना)।

5. SIPDA योजना के तहत दिव्यांगजनों में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP]- 2016

6. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के तहत संचालित योजनाएँ-

- दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना (स्वरोजगार हेतु 50 लाख तक रियायती ऋण उपलब्ध कराना)।
- विशेष माइक्रो-फाइनेंस योजना (लघु व्यवसाय हेतु रियायती ऋण उपलब्ध कराना)
- दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता योजना-
- NGO के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

Scanned by CamScanner

7. National Trust for Welfare of Persons with Disabilities के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ।

8. दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए Pre Matric / Post Matric छात्रवृत्तियों, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, निःशुल्क योजना।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner